

शोकोदगार

प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र की कार्यवाही 3 दिन के अवकाश के बाद आज शिमला में फिर शुरू हुई। सदन की बैठक शुरू होते ही पूर्व विधायक राम रत्न शर्मा के निधन पर शोक व्यक्त किया गया। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सदन में शोक प्रस्ताव रखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राम रत्न शर्मा नादौनता विधानसभा क्षेत्र से जुड़े रहे और बाद में इस विधानसभा क्षेत्र का नाम बदलकर बड़सर हुआ। उनका जन्म 28 जनवरी 1937 को हमीरपुर जिला के चकमोह में हुआ था। वे लंबे समय से राजनीति और सामाजिक कार्यों से जुड़े रहे तथा सामाजिक जीवन में लगातार सक्रिय रहे। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि राम रत्न शर्मा भाजपा और उससे पहले आरएसएस के समर्पित कार्यकर्ता रहे। उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि आंदोलन में राम रत्न शर्मा की सक्रिय भूमिका रही। विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने कहा कि राम रत्न शर्मा दो बार भाजपा के विधायक रहे और वे कर्मठ व जुझारू व्यक्ति थे। राजेश धर्माणी ने कहा कि राम रत्न शर्मा अपने इरादों के पक्के थे और जो ठान लेते थे, उसे समर्पित भाव से पूरा करते थे। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने भी खुद को शोकोदगार में शामिल करते हुए कहा कि दिवंगत राम रत्न शर्मा के योगदान याद किया।

प्रश्नकाल

प्रदेश के सरकारी स्कूलों में जे.बी.टी. और टी.जी.टी. के कुल 5 हजार 2 सौ 9 पद खाली हैं। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान आज विधायक पवन कुमार काजल, हंसराज, जीतराम कटवाल और दलीप ठाकुर के सवाल के लिखित जवाब में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जे.बी.टी. के सबसे अधिक 4 हजार 19 पद रिक्त हैं। शिक्षा मंत्री ने बताया कि 31 जुलाई 2026 तक टी.जी.टी. के कुल एक हजार एक सौ 90 पद रिक्त थे और इनमें से 7 सौ 64 पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान में बैचवाइज़ भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से भरे जा रहे टी.जी.टी. के 13 पदों के अलावा किसी अन्य पद के लिए बैचवाइज़ भर्ती प्रक्रिया जारी नहीं है। विधायक केवल सिंह पठानिया के सवाल के लिखित जवाब में स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने बताया कि प्रदेश में एड्स नियंत्रण संस्थाओं में काम कर रहे कर्मचारियों को नियमित करने का राज्य सरकार को कोई विचार नहीं है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में इन संस्थाओं में 4 सौ 14 कर्मचारी कार्यरत हैं, जो संबंधित गैर सरकारी संस्थाओं के अधीन साल दर साल अनुबंध समझौते के अनुसार सेवाएं दे रहे हैं। विधायक हरदीप सिंह बावा के सवाल के लिखित जवाब में स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि प्रदेश में आशावर्करों को भविष्य में नियमित करने के लिए सरकार कोई नीति नहीं बनाएगी। उन्होंने बताया कि आशावर्कर स्वैच्छिक कार्यकर्ता हैं और आशा कार्यक्रम एन.एच.एम. के दिशा-निर्देशों के तहत चलाया जा रहा है। शांडिल ने कहा कि मौजूदा व्यवस्था के अनुसार आशावर्करों के लिए स्थायी नीति का कोई प्रावधान नहीं है।

राजेंद्र राणा

प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता व पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने सुक्खू सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस द्वारा चुनाव के समय जनता को दी गई 10 गारंटियां अभी भी धरातल पर उतरने का इंतज़ार कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 18 से 60 वर्ष तक की महिलाओं को प्रतिमाह 15 सौ रुपये देने, युवाओं को हर साल एक लाख रोजगार, 3 सौ यूनिट मुफ्त बिजली सहित बड़े-बड़े वायदे कर सत्ता हासिल की है, लेकिन अब यही गारंटियां सरकार के लिए गले की फांस बन गई हैं। राजेंद्र राणा ने कहा कि 4 साल के कार्यकाल के बाद भी सुक्खू सरकार इन गारंटियों को पूरा करने की बजाय बहाने बना रही है, जिससे स्पष्ट है कि ये वायदे केवल चुनाव जीतने का राजनीतिक हथकंडा थे। हिमकेयर योजना को लेकर राजेंद्र राणा ने कहा कि जिस योजना ने प्रदेश के आम

परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा का भरोसा दिया था, उसकी व्यवस्था को भी सरकार ने कमज़ोर कर दिया है। उन्होंने 10 गारंटियों पर तत्काल श्वेत पत्र जारी कर हर गारंटी की स्थिति सार्वजनिक करने की सरकार से मांग की है।

दूध मूल्य

सिरमौर ज़िला किसान सभा की एक बैठक आज नाहन में आयोजित हुई। किसान सभा के राज्य सचिव राकेश सिंघा बैठक में विशेष रूप से मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में दूध उत्पादकों को समय पर दूध का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जिससे किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राकेश सिंघा ने मिल्क प्लांट में दूध की जांच के लिए आधुनिक उपकरण स्थापित करने की सरकार से मांग की है।

राकेश सिंघा ने कहा कि खेती की लागत बढ़ने से किसान कर्जदार हो रहा है और उनकी फसलों का उचित समर्थन मूल्य भी नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने बिजली के स्मार्ट मीटर लगाए जाने से आ रही परेशानियों का मुद्दा भी उठाया।
